सर्वहारा दृष्टिकोण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-28 अंक-13 7 से 21 जुलाई, 2013 मुख्य संपादक - कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती मूल्य : 2 रुपये

क्या कम नहीं की जा सकती थी उत्तराखण्ड की यह तबाही

कितने मरे, कितने लापता हैं, कितने अभी भी दुर्गम इलाकों में फंसे हुए हैं इसका पूरा ब्यौरा दो हफ्ते बाद भी नहीं दे सकी सरकार

प्रशासनिक लापरवाही का इससे बड़ा नमूना और क्या होगा

उत्तराखण्ड के केदारनाथ मन्दिर परिसर में सड़ रहे शवों के ढेर, पहाड़ के धंसने की भयावह तस्वीरें, नदियों में आई विनाशकारी बाढ़ के चित्र अखबारों के पन्नों या टी.वी. की स्क्रीन पर देख कर सारे देश के लोग सिहर उठे। राहत और बचाव दल अभी तक भी बहुत कम जगहों तक ही पहुँच पाए हैं। तीर्थ स्थानों, पर्यटन केन्द्रों में 23 जून तक लगभग 60 हजार लोगों के फंसे होने की खबर प्रशासन ने दी थी। विध्वस्त नौ जिलों के सैकड़ों गाँवों के आम लोगों की क्या दशा हुई इस बारे में कुछ नहीं बताया गया है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार विशेषकर रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी जिलों के कम से कम 60 गाँवों का कोई अस्तित्व ही खोजने से नहीं मिल रहा है। असल संख्या इससे कई गुना ज्यादा है इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। जो अभी भी बच गए हैं वे भी खुले आकाश के नीचे रात्रि की भयंकर ठंड में खाने और पीने के पानी के अभाव में तिल-तिल कर मरने के इंतजार की घड़ियाँ गिन रहे हैं। वैसे भी ध्वस्त दुर्गम पहाड़ी रास्तों को ठीक करके जिस गति से बचाव कार्य चल रहा है उससे और भी बहुत से लोगों को बचाने की संभावना लगातार कम होती जा रही है। चन्द हेलिकॉप्टरों को लेकर मिलिट्री द्वारा केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे तीर्थस्थानों से कुछ पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाये जाने के बावजूद बहुत से लोग अभी भी फंसे हुए हैं। कांग्रेस-नीत

(शेष पृष्ठ 2 पर)

सरकारी उदासीनता की वजह से उत्तराखण्ड में असंख्य लोगों की जान गई

सोशलिस्ट यूनिटी सेण्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) के महासचिव कॉमरेड प्रभाष घोष ने 20 जून को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा:

उत्तराखण्ड में 16-17 जून को अचानक आई बाढ़, बादल फटने और जमीन धंसने से जानमाल की जो भयंकर हानि हुई है उसे काफी हदतक कम किया जा सकता था, यदि प्रभावकारी सूचना तन्त्र और आपदा प्रबंधन की व्यवस्था रहती। आम लोगों तक सही समय पर चेतावनी पहुँच जाती तो हजारों हजार जाने बच सकती थी। जान-माल का भारी नुकसान और लोगों का हाहाकर राज्य प्रशासन की घोर विफलता की वजह से कई गुना बढ़ गया है। राज्य और केन्द्रीय सरकार 'तीन दिन का शोक' मनाने के माध्यम से चाहे जितने भी घड़ियाली आंसू बहाने की कोशिश क्यों न करें, वह इस मुजरिमाना लापरवाही के कसूर से किसी भी तरह माफी की हकदार नहीं है।

इस प्रलयकारी आपदा में हजारों लोग मारे गए हैं और 60 हजार से ज्यादा लोग दुर्गम स्थानों में फंसे हुए हैं। हम मांग करते हैं कि इन फंसे हुए लोगों तक पर्याप्त भोजन, पीने का पानी और राहत सामग्री पहुँचाने के लिए सरकार पूरी ताकत झोंक दे। दुबारा बारिश और बाढ़ आने से पहले ही सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने की हर तरह की व्यवस्था करे। भारी संख्या में पशुओं और मनुष्यों के शवों के चारों तरफ पड़े रहने की वजह से महामारी फैलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। महामारी को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार को तुरन्त उचित कदम उठाने चाहिएं। भारी जनहानि और विनाशलीला की व्यापकता के मद्देनजर केन्द्र सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना चाहिए।

एसयूसीआई(सी) ने सभी कार्यकर्ताओं को लोगों से तुरन्त आर्थिक मदद जुटा कर और उत्तराखण्ड के विभिन्न इलाकों में चिकित्सा शिविर लगा कर प्रभावित लोगों की मदद करने का निर्देश दिया है।

उत्तराखण्ड में आपदा पीड़ितों के लिए मेडिकल कैम्प शुरू

मेडिकल सर्विस सेण्टर के सह सचिव और डिजास्टर सैल के इंचार्ज डॉ. अंशुमान मित्रा ने रुद्रप्रयाग स्थित चिकित्सा शिविर से 30 जून को निम्नलिखित रिपोर्ट जारी की:

''मेडिकल सर्विस सेण्टर की केन्द्रीय कमेटी ने उत्तराखण्ड में बादल फटने, अचानक आई बाढ़ और जमीन धंसने की तबाही के बाद रुद्रप्रयाग के प्रभावित जिले को केन्द्र कर प्रथम मेडिकल रिस्पोंस टीमें भेज कर पीड़ितों को राहत पहुँचाने का काम शुरू किया। दो सदस्यीय सर्वे टीम ने 23 जून, 2013 से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इसके लिए वे चन्द्रापुरी तक गए। एमएससी के सहसचिव और डिजास्टर रिस्पोंस सैल के इंचार्ज डॉ. अंशुमान मित्रा के नेतृत्व में विभिन्न राज्यों से आए डाक्टरों की एक 6 सदस्यीय पायलॉट मेडिकल टीम मेडिसन, ट्रॉमा और साइकॉलोजिकल ट्रॉमा की समस्याओं से निपटने के लिए 28 जून को रुद्रप्रयाग बेस कैम्प स्थापित करने के लिए पहुँची जिसने रुद्रप्रयाग जिले के जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग कस्बे में विकास भवन, मेन मार्किट कॉम्पलैक्स के सामने 29 जून को काम शुरू कर दिया।

दूसरे दिन यानी 30 जून को दो कैम्प लगाए गए। एक रुद्रप्रयाग में बैस कैम्प और दूसरा मोबाइल कैम्प सिल्ली (अगस्त मुनि के नजदीक)में लगाया गया। रुद्रप्रयाग के बेस कैम्प में लगभग 83 मरीजों की जांच की गई और इलाज किया गया। ये टाऊन से और चोपरा, अंशारी, हिन्दनाग, चन्द्रापुरी सिमरी और रतुरा आदि आस-पास के लगभग 12 गाँवों से आए थे। इनमें पुरुष और महिलाएं दोनों ही शामिल थे। सिल्ली के मोबाइल कैम्प में लगभग 47 मरीजों की जाँच और इलाज किया गया जो कस्बे से और बुदुली, मोहांखाल, कुमरी आदि आस-पास के लगभग पाँच गाँवों से आए थे। तीसरे दिन यानी 1 जुलाई को 71 मरीजों का इलाज चोपड़ा में लगाये गए मोबाइल कैम्प में 5 डॉक्टरों

(शेष पृष्ठ 7 पर)

प्राकृतिक गैस के दाम दुगने करने का एसयूसीआई(सी) द्वारा कड़ा विरोध

एसयूसीआई(सी) के महासचिव कॉमरेड प्रभाष घोष ने 29 जून 2013 को जारी एक बयान में कहा:

फर्टिलाइज़र और बिजली उत्पादन के लिए एक बहुत जरूरी चीज, प्राकृतिक गैस के दाम बढ़ाने के एकतरफा और मनमाने ढंग से उठाए गये घोर कठोर कदम का हम कड़ा विरोध करते हैं। मुकेश अम्बानी की रिलायन्स इण्डस्ट्रीज की ब्लैकमेलिंग के आगे घुटने टेकते हुए प्राकृतिक गैस के दाम 4.2 डॉलर से 8 डॉलर प्रति एमबीटीयू (मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट) कर दिए गए हैं। रिलायन्स इण्डस्ट्रीज केजी-डी 6 गैस बेसिन में प्राकृतिक गैस का उत्पादन बताए गए टारगेट से जानबूझ कर तब तक कम रख रही थी जब तक कि सरकार इस बेतहाशा दाम बढ़ोतरी की उसकी मांग के आगे झुक नहीं गई। यह भी पता लगा है कि सरकार की योजना है कि प्रति एमबीटीयू गैस के दाम पहले

(शेष पृष्ठ 7 पर)

उत्तराखण्ड आपदा पीड़ितों के लिए एसयूसीआई(सी) के दिल्ली कार्यालय से राहत सामग्री और मेडिकल टीम को रवाना करने के लिए लाल झण्डी दिखाते हुए कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती

उत्तराखण्ड की यह तबाही ..

(पृष्ठ 1 का शेष)

राज्य सरकार का कोई वजूद ही नजर नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को यह मानने को मजबूर होना पड़ा कि आपदा का मुकाबला करने के लिए कंप्ट्रोलर एण्ड ऑडिटर जनरल (सी.ए.जी.) और आपदा प्रबन्धन दफ्तर ने दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में जिस तरह की आपातकालीन व्यवस्था कायम करने के लिए बार-बार सिफारिश की थी उसका न्यूनतम भी उन्होंने नहीं किया। (टाइम्स ऑफ इण्डिया 22 जून 2013) बादल फटने से हुई भारी वर्षा की वजह से नदी में उफान आ सकता है और पहाड़ धंस सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसी वजह से ही इस तरह की भयंकर आपदा आ सकती है यह कहा नहीं जा सकता।

उत्तराखण्ड की वर्तमान शासक कांग्रेस और पूर्ववर्ती शासक बी.जे.पी. के नेताओं की मदद से किसी भी नीति नियम की परवाह न करते हुए राज्य के पहाड़ी क्षेत्र मे सभी जगह भू-माफिया प्रोमोटरों ने असंख्य बहुमंजिला इमारतें बनाई हैं। पर्यटन उद्योगों के नाम पर कृत्रिम ढंग से यहाँ-वहाँ टूरिस्ट स्पॉट तैयार किए गए हैं। सरकारी आँकड़ों के मुताबिक 2005 से 2012 तक उत्तराखण्ड में पर्यटकों की संख्या चौगुनी हो गई है, पर्यटन केन्द्र दुगुने से भी ज्यादा हो गए हैं। जिसकी वजह से बहुमंजिले होटल, धर्मशाला इत्यादि यहाँ-वहाँ बनाये गए हैं। यहाँ तक कि पहाड़ी नदी के किनारे या झरने का रास्ता घुमा कर होटल बनाए गए हैं। पहाड़ पर बहुमंजिले निर्माण वर्जित होने के बावजूद यह सब काम बेरोकटोक चल रहा है। यहाँ तक कि स्वयंसेवी धार्मिक संस्थाएं भी सरकारी नेताओं की वोट बैंक राजनीति का लाभ उठा कर सात-आठ मंजिले मकान बना कर बैठी हैं। ये सब पर्यटन केन्द्र बनाने के लिए भारी संख्या में पेड़ काटे गए हैं। मकान की दीवारें खड़ी करने के लिए नदी किनारे डायनामाइट लगा कर पत्थर तोड़ कर कंक्रीट तैयार किया गया है। जिसकी वजह से पहाड़ के पत्थर अपनी जगह से हिल गए हैं, पेड़ काटने की वजह भूमि कटाव बढ़ा है। कम समय में भारी वर्षा से जब भारी मात्रा में पानी पहाड़ से बह कर नीचे आया तो मीलों मील तक उसने तबाही मचा दी। असंख्य जनपदों का नामो-निशान तक मिट गया। पर्यटन कारोबारियों और नेताओं द्वारा धन बल के जोर से नियम कानूनों की धज्जियाँ उड़ाये जाने का खामियाजा हजारों हजार लोगों को अपनी जान गवां कर भरना पड़ा है। पनबिजली उत्पादक लॉबी ने तो और भी विनाशकारी काम किया है। सिर्फ अलकनन्दा, मन्दाकिनी और भगीरथी-गंगा की इन तीन उपनदियों पर 10 से लेकर 100 मेगावॉट क्षमता के 70 पनबिजली केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इनके अलावा भी बहुत से केन्द्र हैं। इनके लिए पहाड़ों में विस्फोट करके जलाशय बनाए गए हैं। अंधाधुंध जंगल काटे गए हैं। नदी-नालों और पहाड़ी झरनों का रास्ता 6 लाख 40 हजार 247 मीटर बदला गया है। आँकड़े बताते हैं कि उत्तरकाशी जिले में 2005 से लेकर विगत साल सालों में इन पनबिजली केन्द्रों के बनने की वजह से पूरे पहाड़ पर 27 बार अचानक बाढ़ का प्रकोप हुआ है। इनमें से तीन ने भयंकर तबाही मचाई थी। फिर भी इससे पहले के 27 सालों में सिर्फ एक बार अचानक बाढ़ से भारी क्षति हुई थी। सरकारी विद्युत केन्द्रों के साथ साथ गैर सरकारी निजी मालिकाने वाले केन्द्र भी हैं। इस क्षेत्र में करोड़ों करोड़ रुपया लगाया गया है। पन बिजली में विदेशी निवेश भी किया गया है। कांग्रेसी और भाजपाई नेता इन बिजली कारोबारियों से करोड़ों करोड़ रुपए कमा रहे हैं। पर्यावरण वैज्ञानिक इस विनाशलीला का अब तक जितना विश्लेषण कर पाए हैं, उसके आधार पर वे कह रहे हैं कि इस तरह से काफी संख्या में पन बिजली केन्द्रों की स्थापना, बांध और नदी-नालों व झरनों के जलप्रवाह को बदलना इस विनाशलीला का एक महत्वपूर्ण कारण है।

आपदा का मुकाबला करने की बड़ी-बड़ी बातें करते हुए हजारों करोड़ रुपए खर्च करके केन्द्रीय सरकार ने नेशनल डिसास्टर मैनेजमेण्ट अथोरिटी (एनडीएमए) और इसके तहत नेशनल डिजास्टर मैनेजमेण्ट फोर्स (एन.डी.एम.एफ.) का गठन किया था। एन.डी.एम.ए. के चेयरमेन स्वयं प्रधानमंत्री हैं और वाइस चेयरमेन आंध्र प्रदेश के कांग्रेसी विधायक शशीधर रेड्डी ही एन.डी.एम.एफ. के संचालक हैं। पदाधिकारी होने के नाते उन्हें केबिनेट मंत्री का दर्जा हासिल है। एन.डी.एम.एफ. के 8 सदस्यों को उपमंत्री का दर्जा हासिल है। इनके पीछे सरकार भारी मात्रा में धन खर्च करती है। लेकिन यह भारी भरकम एन.डी.एम.एफ. इस भूचाल संभावित पर्वतीय उत्तराखण्ड में एक बटालियन कायम करने को पैसे की कमी का बहाना बना कर दो सालों से टालती आ रही थी। इस भयंकर आपदा की खबर पाकर एन.डी.एम.एफ. वाहिनी ने उत्तराखण्ड पहुँचने में ही लगभग दो दिन लगा दिए। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एन.डी.एम.एफ. का काम था बचाव कार्य को समन्वित करना। प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं कि समन्वय का यह मामला ही उत्तराखण्ड में पूरी तरह नदारद था। असल में जो जनमुखी नजरिया रहने से यह काम संभव हो सकता था इस सरकार से उसकी अपेक्षा करना ही फिजूल है।

सरकार की मदद से मुनाफाखोर मालिकों द्वारा पर्यावरण को अंधाधुंध नष्ट किया जाना ही उत्तराखण्ड की इस आपदा का एक प्रमुख कारण है यह आज स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। दुनिया के अधिकतर देशों में ही धन-कुबेर पूँजीपतियों का अकूत मुनाफा सुनिश्चित करने के लिए ही कल-कारखानों में पर्यावरण नियमों की कोई परवाह ही नहीं की जा रही है। पर्यावरण को अंधाधुंध नष्ट किया जा रहा है। यही वजह है कि दुनिया की बहुत सी जगहों पर आबो-हवा का अस्वाभाविक परिवर्तन हो रहा है। हिमालय पर्वतमाला का स्वाभाविक पर्यावरण भी इसी वजह से दूषित हो रहा है। देश में लगभग सभी जगह विकास के नाम पर पर्यावरण को दूषित किया जा रहा है। देश में लगभग सभी जगह विकास के नाम पर पर्यावरण की विनाशलीला चल रही है। इसके खिलाफ कहीं भी लोग सिर उठाते हैं तो सरकार पुलिस-मिलिट्री लगा कर आन्दोलन का दमन करती है। कॉरपोरेट संवाद माध्यम हो-हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं कि विकास का विरोध नहीं चलेगा। लेकिन विकास का मायने ही अंधाधुंध पर्यावरण ध्वस्त करना नहीं है, इसका वास्तविक उदाहरण एक समय मानवजाति ने सोवियत समाजवाद के अन्दर देखा था। बड़े पैमाने पर काम-कार्रवाइयों में आम लोगों की भागीदारी के बावजूद पर्यावरण की रक्षा करना अत्यंत महत्वपूर्ण बात थी। उत्पादन का उद्देश्य वहाँ मुनाफा नहीं था इसी वजह से यह काम संभव हो सका था। अधिकतम मुनाफे वाली पूँजीवादी व्यवस्था में यह असंभव है। उत्तराखण्ड की इस भयंकर विनाशलीला ने एक बार पुनः दिखा दिया है कि मुट्ठी भर अमीरों का धन का लोभ किस प्रकार पूरी मानवजाति के सर्वनाश को न्योता दे रहा है।

विपत्ति में पड़े लोगों को बचाना और उन तक राहत पहुँचा देना ही आज की फौरी जिम्मेदारी है। **एस.यू.सी.आई(सी) सभी राज्यों में राहत जुटाने में लगी है। प्रभावित इलाकों में राहत और दवाईयाँ लेकर स्वयंसेवकों ने काम शुरू कर दिया है। रूद्रप्रयाग में पार्टी ने एक स्वयं सेवबी संस्था मेडिकल सर्विस सेण्टर तथा स्थानीय लोगों की मदद से एक मेडिकल कैम्प स्थापित किया है। इस कैम्प को केन्द्र करके डॉक्टरों और स्वयंसेवकों की मोबाइल टीमें उन दुर्गम इलाकों में स्थानीय लोगों को चिकित्सा सहायता पहुँचा रही हैं जहाँ अभी तक प्रशासन ने पीड़ित लोगों की सुध ही नहीं ली है।** इसके साथ ही देश के लोगों तक यह संदेश पहुँचा देने की भी जरूरत है-पूँजीपतियों के मुनाफे के स्वार्थ में लोगों के जिन्दा रहने के परिवेश और पर्यावरण को ध्वस्त किए जाने के खिलाफ जोरदार आन्दोलन गठित करने के कर्त्तव्य की जरा सी भी अवेहलना नहीं की जा सकती है। नहीं तो हमें इसकी कीमत चुकाते जाना होगा।

अखबारी कतरनें

राष्ट्रीय सहारा

देहरादून । रविवार • 30 जून • 2013

मरीजों का स्वास्थ्य जांचा

रुद्रप्रयाग। सोसलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया के सहयोग से आपदा पीड़ितों के लिए चिकित्सा शिविर में दो सो मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाइयां वितरित की गई। विकास भवन के समीप सोसलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया की मेडिकल सर्विस सेंटर इकाई ने आपदा पीडितों के लिये निःशुल्क चिकित्सा शिविर कर आयोजन किया। जिसमें, सर्विस सेंटर के चिकित्सक अंशुमन मिला के निर्देशन में चिकित्सकों की टीम ने दो सौ मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर औषधियां वितरित कीं। शिविर के आपदा प्रबंधन इंचार्ज मुकेश सेमवाल ने बताया कि संस्था द्वारा दैवीय आपदा से पीडित लोगों की सहायता में हाथ बंटाते हुए सहायता की दृष्टि से चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष राकेश नौटियाल, भाजपा जिलाध्यक्ष विजय कप्रवाण, पालिका सभासद दीपांशु भट्ट, रामलाल चौधरी, हेमंत बर्त्वाल, घनश्याम आदि मौजूद थे।

SUNDAY अमर उजाला

देहरादून। रविवार। 30 जून 2013

प्रभावितों के लिए हेल्थ कैंप आयोजित

रुद्रप्रयाग। जिले में आई दैवी आपदा को देखते हुए विभिन्न संस्थाओं की ओर से नगर मुख्यालय में मेडिकल रिलीफ कैंप लगाए जा रहे हैं। रविवार को कोटेश्वर स्थित शंकराचार्य माधवाश्रम धर्मार्थ चिकित्सालय में एक माह का निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर शुरू हो गया है। अस्पताल के ट्रस्टी महंत शिवानंद गिरि महाराज ने बताया कि शिविर में सभी सेवाएं निःशुल्क हैं। वहीं अखिल भारतीय चिकित्सक संगठन द्वारा भी रुद्रप्रयाग में डॉ. अंशुमन मित्रा के नेतृत्व में मेडिकल कैंप लगाया गया है। कैंप के पहले दिन लगभग 200 मरीजों का निःशुल्क चेकअप किया गया।

खाद्य सुरक्षा के नाम पर राशन व्यवस्था को ध्वस्त करने का षड़यन्त्र

जन्तु-जानवरों के लिए सिर्फ पेट भरना ही काफी है। लेकिन मनुष्यों के लिए इतना ही काफी नहीं है। फिर शरीर और चिन्तन शक्ति की स्वाभाविक सुरक्षा और विकास की जरूरत के साथ खाद्य विविधता का सम्बन्ध है। सिर्फ नमक-मिर्च के साथ एक प्लेट चावल या एक दर्जन रोटी खाने से ही यह नहीं कहा जा सकता कि बढ़िया खाना हुआ। लेकिन देश के बहुत नामी-गिरामी नेता-मंत्रियों के हावभाव देखने से लगता है कि वे मनुष्य को पेट भरू एक जानवर के रूप में ही देखते हैं। इसीलिए पशु की तरह काम लेने के लिए पेट की खातिर कैलोरियों का हिसाब लगाते हैं। खाद्य सुरक्षा बिल को लेकर वर्तमान में तथा आजादी के बाद से ही पेट की भूख मिटाने की चर्चा-बहस चलती आ रही है। यह चलती ही रहेगी। इससे चर्चा-बहस का ढंग बदलेगा लेकिन पेट की भूख बरकरार रहेगी।

ज्ञानियों की बुद्धि बहुत ही सूक्ष्म, इतनी सूक्ष्म कि वह है भी या नहीं, बहुत बार यह समझा ही नहीं जा सकता है। कागजी रिपोर्टों की बहुत सी लड़ाइयों के बाद भी देश से कागजी आंकड़ों में भी अनाहारी लोगों का कोई उद्धार नहीं किया जा सका है। अंततः रिपोर्टों में गरीबी दूर करने के प्रयास में कमिशन आदि कुछ दूर तक आगे भी बढ़े थे। लेकिन विवाद उठा कि 2004-05 से 2009-10 के बीच खाद्य कैलोरी हासिल करने की मात्रा घटी है। यह कमी उल्लेखनीय रूप में हुई है। कम होने की ही बात है क्योंकि रोजाना 20 रुपये खर्च करने की भी क्षमता जिनकी नहीं है वे खाएंगे क्या? (अर्जुन सेनगुप्ता कमेटी के मुताबिक 77% लोग रोजाना 20 रुपये खर्च करने की क्षमता भी नहीं रखते हैं।) इन मामूली पैसों से दूध, रोटी, चावल या दाल सब्जी की तो बात छोड़िये, दो जून की रूखी-सूखी रोटी मिलना भी मुश्किल है।

दुनिया के गरीबों का एक चौथाई हिस्सा भारत में रहता है। अशिक्षित, बेइलाज, रोगग्रस्त, कुपोषित, बीमार लोग करोड़ों की संख्या में हैं। लाखों बच्चे जन्म लेने के बाद ही मर जाते हैं। आधी से ज्यादा महिलाएं कुपोषण की शिकार हैं। लोगों को न तो पीने का पानी उपलब्ध है, न ही शौचालय। नेशनल सैम्पल सर्वे रिपोर्ट 2011 में मानव विकास सूचकांक समीक्षा में कहा गया है, आधे भारतीयों परिवारों में कोई भी शौचालय नहीं है। (2008-09 तक का सर्वेक्षण) ग्रामीण इलाकों में यह दर 75 प्रतिशत है। फिर इनमें दलितों, मुस्लिमों, जनजाति समुदायों की हालत तो और भी भयावह है। यही तो है देश! और रोजगार? 94% लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। सिर्फ 6% संगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। आजादी के बाद से आज तक मुख्यतः कांग्रेस और बाद में भाजपा जैसे अखिल भारतीय और अन्यान्य क्षेत्रीय दलों के शासनकाल में यह असहनीय हालत पैदा हो गयी है। इस विकास (!) के पीछे सीपीएम का योगदान भी भुलाया नहीं जा सकता है। इन भूखे नागरिकों को लेकर ही हजारों परीक्षण-निरीक्षण हो रहे हैं। जीवन के लिए बाकी सब कुछ गया भाड़ में। भूख की आग से छटपटाते लोग आज नेताओं के कथित विकास की कहानी सुनते-सुनते ही सो जाते हैं। इन लोगों का भी निश्चित ही वोट के बाजार में एक मूल्य है। इसलिए चुनावी मौसम में देखा जाता है कि सरकार इनके प्रति कितनी दरियादिल और हमदर्द है। मानो इनके लिए ही खाद्य सुरक्षा बिल लाने का इंतजाम किया गया हो। इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बदले या राशन में खाद्य आपूर्ति के बदले खाद्य अनुदान(सब्सिडी) का पैसा ग्राहकों को सीधा नगद दिया जाएगा। इस सूक्ष्म बुद्धि का कारनामा कमिशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एण्ड प्राइसेज ने किया है। उनके मतानुसार इस पद्धति को क्रियान्वित कर सकने से सरकार का खर्च काफी हद तक कम हो जाएगा। सरकार और ग्राहकों के बीच से डीलर, परिवहन के लोग इत्यादि बिचौलियों के जमघट को एक तरफ करते हुए खाद्य की कीमत सीधे ग्राहकों के पास पहुँच जाएगी। चोरी-भ्रष्टाचार बन्द हो जाएगा जिसका हक उसी को मिलेगा।

लेकिन यहाँ बता देना उचित है कि राशन में अनुदान देकर खाद्य आपूर्ती करने की व्यवस्था के चालू होने की एक पृष्ठभूमि है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। मौजूदा व्यवस्था में सरकार चावल, गेहूँ, इत्यादि का समर्थन मूल्य देकर किसानों से अपनी खुद की संस्था एफसीआई के माध्यम से खरीदती है। इससे डिस्ट्रेस सेल के प्रकोप से कुछ हद तक किसान बच सकते हैं। तमाम खाद्य न्यायसंगत दाम देकर खरीद लेने से किसान कुछ हद तक सुरक्षित होंगे, बचे रह सकेंगे। इसके बाद वही खाद्य राशन में देने से यही किसान राशन में सस्ते में खाद्य पदार्थ ले सकेंगे। इन दो अनुदानों के अलावा कृषि उपकरणों के लिए भी किसानों को एक तरह का अनुदान मिलता है। खाद, बीज, कीटनाशक, इत्यादि सस्ते में सरकार देती थी। सब मिलाकर गरीब लोगों का न्यूनतम खाद्य तक एकाधिकारी व्यापारियों या कालाबाजारियों द्वारा जैसे कि हड़प न लिया जाए। इनके हाथों से कुछ हद तक रक्षा करना भी राशन व्यवस्था का एक उद्देश्य था। जनकल्याणकारी राज्य का दावेदार भारत अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिस्थिति के दबाव में यह करने के लिए बाध्य हुआ था। दूसरे विश्वयुद्ध के बाद के समय समाजवाद का जयघोष गूँज रहा था। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा की गारण्टी समाजवाद ने दी थी। इसके चलते देश-देश में मजदूर-किसानों के अन्दर समाजवाद के प्रति प्रबल आकर्षण दिखाई दे रहा था। इस प्रभाव से जन साधारण को मुक्त करने और संभावित मजदूर क्रान्ति से भारतीय पूँजीवाद की रक्षा करने या पूँजीवादी शोषण की जलन को कुछ कम करने के लिए एक मानवीय मुखौटा सरकार को पहनना पड़ा था। देश के अन्दर एक भय भी था। 1943 के अकाल जैसी आपदा का भय। उस समय बंगाल के 15 लाख लोग भुखमरी की वजह से मर गए थे। जमाखोरों, कालाबाजारियों के हाथ से रक्षा करने के लिए राशन व्यवस्था आई थी। चावल, गेहूँ, चीनी, केरोसीन पर एक नियंत्रण लगाकर राशन दिया जाता था। महात्मा गांधी के तीव्र विरोध की वजह से आजादी के बाद अंततः यह नीति निरस्त कर दी गई। महात्मा गांधी का वक्तव्य था कण्ट्रोल छल-कपट को जन्म देता है। सच्चाई को छिपाने का रास्ता दिखाता है, कालाबाजारी की तीव्रता को बढ़ाता है, कृत्रिम अभाव पैदा करता है। इसके अलावा इन्सान को नीचे गिराता है। जनसाधारण की पहलकदमी को मार देता है, आत्मनिर्भरता को खत्म कर देता है और उन्हें दया का मोहताज बना देता है। (दि हिन्दू: 11 मई 2013)

राशन और कण्ट्रोल व्यवस्था समाप्त करने के फलस्वरूप बाजार के उपर जमाखोरों और कालाबाजारियों का दबदबा फिर से इतना बढ़ गया, इतना कृत्रिम अभाव पैदा किया गया, इतनी महंगाई बढ़ी कि सरकार को 1949 में राशन व्यवस्था को पुनः बहाल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद 1952-54 में ही खाद्य उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ अन्यान्य उत्पादन नियन्त्रित रहने और बेहतर राशन व्यवस्था के जोर से बाजार पर नियन्त्रण रहने के फलस्वरूप दाम कुछ कम हुए थे। खाद्य भण्डारण के सरकारी उद्यम, खाद्य आवाजाही पर सरकारी नियंत्रण की निषेधाज्ञा समाप्त कर दी गई। परिणामतः फिर से कालाबाजारी-जमाखोरी बढ़ने से संकट घनघोर हो गया। महंगाई भी बढ़ गई। 1957 में अशोक मेहता परिचालित फूड ग्रेन्स इन्क्वायरी कमेटी ने यह सब देख कर फैसला लिया कि घबराने की कोई बात नहीं है। मनी सर्कुलेशन में बढ़ोतरी, उद्योगों के विकास, शहर निर्मित होने की विकास धारा, व्यापार वाणिज्य में निवेश की वृद्धि से खरीद क्षमता में बढ़ोतरी हुई है। अर्थात लोगों की खरीद शक्ति बढ़ी है। इसीलिए चीजों के दाम बढ़े हैं। अवश्य इतना ही सब नहीं। इसके साथ जुड़ गई है व्यापारियों की जमाखोरी में बढ़ोतरी, सट्टा बाजार में रुपया लगाना। परिणामतः महंगाई बढ़ी हैं। 1955 के बाद से ही मांग के मुकाबले आपूर्ति भी घटी। कमिशन की रिपोर्ट में कहा गया मुद्रास्फीति और खाद्य कमी के बीच सामंजस्य रखने के लिए सरकार की सुसमन्वित नीति बनाने और उसको आधार बना कर इन सब समस्याओं के प्रतिरोध करने की कोई भी व्यवस्था ही नहीं है। कभी उत्पादन के दाम बहुत कम, कभी फिर बहुत ऊँचे हो जाते हैं। इसका मुकाबला करना होगा, एक स्थायित्व चाहिए। इस परिस्थिति के फलस्वरूप 1956 के अक्टूबर से 1957 के सितम्बर के बीच सरकार ने 10 हजार राशन दुकानें कायम की थीं। अर्थात फिर से बाजार नियंत्रण और राशन व्यवस्था चालू हुई। 1957 के बाद 1959 से 1966 का रक्तरंजित खाद्य आन्दोलन हुआ। शहीदों के आत्मबलिदानों के चलते पश्चिम बंगाल में खाद्य जन-वितरण प्रणाली को, बाजार पर नियंत्रण की व्यवस्था को चालू रखने के क्षेत्र में ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी। सारा भारतवर्ष भी उसके द्वारा उपकृत हुआ था।

पूँजीवादी नियम के अनुसार सर्वोच्च मुनाफा ही उत्पादन का उद्देश्य है लोगों की जरूरत नहीं। कर्म क्षमताशील लोगों के पास काम नहीं है। लोग जमीन से विछिन्न होते जा रहे हैं। मजदूर बनते जा रहे हैं। कारखानों में छंटनी, तालाबंदी, ले ऑफ जारी है। औद्योगिक संकट से अर्थव्यवस्था डगमगा रही है। इस सीमाहीन संकट की पुनरावृत्ति द्वितीय विश्वयुद्ध के समय से किसी भी अंश में कम नहीं है। एक समीक्षा में देखा गया कि गत 6 साल में भुखमरी से और इलाज किए जा सकने वाले मामूली रोगों से पूरी दुनिया में मरने वाल बच्चों की संख्या द्वितीय विश्व युद्ध के 6 साल में मारे गए लोगों के बराबर है। प्रति तीन सैकेण्ड में एक मानव जीवन जो अभी शुरू ही हुआ था वह निर्ममतापूर्वक समाप्त हो जाता है ठीक इतने ही समय में पूरी दुनिया में 120000 डॉलर युद्धास्त्रों के निर्माण के लिए खर्च होते हैं। (ईपीडब्ल्यू: 25-31 जुलाई 2006)

सोवियत समाजवाद तथा विश्व समाजवादी व्यवस्था के पतन के बाद तमाम पूँजीवादी देशों ने जन साधारण के ऊपर शोषण, लूट, आक्रमण तीव्रतर कर दिया है। जनता के लिए खाने की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी, पीने के पानी की जिम्मेदारी, शिक्षा की जिम्मेदारी, रहने के लिए छत की जिम्मेदारी, इलाज की जिम्मेदारी किसी का भी पालन सरकार नहीं कर रही है। सभी कुछ का निजीकरण-व्यापारीकरण करके लाभदायक व्यापार के लिए उपादान तैयार कर देना ही सरकार का काम हो गया है। डब्ल्यू टी ओ की नीति और परिकल्पना के अनुसार पूरी दुनिया ही आज इसी रास्ते पर चल रही है। देश की नहीं, जाति की नहीं, बल्कि पूँजीपतियों की सेवा में सब एक हैं। इसमें कोई दलगत तफर्का नहीं है। भारत सरकार की 'जनकल्याणकारी' राजनीति का आज पर्दाफाश हो गया है। डब्ल्यू टी ओ के हस्ताक्षरकारी 'जिम्मेदार' सदस्य होने के नाते इसे राशन व्यवस्था को धीरे-धीरे समाप्त कर देना पड़ रहा है। इसी क्रम में ही जन वितरण प्रणाली या टार्गेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आया अर्थात सभी को राशन में सभी चीजें देने की जरूरत नहीं है। इसी उद्देश्य से लाया गया बीपीएल, एपीएल। एपीएल बताकर जनसंख्या के एक विशाल हिस्से को अलग कर दिया गया। अतः यह सरकार जब कहती है कि सभी के लिए खाद्य सुरक्षा का नया बिल लाया जा रहा है तब यह नितांत ढोंग के सिवाए और क्या है?

खाद्य पदार्थों के दाम जिस अस्वाभाविक गति से बढ़ रहे हैं, इससे आज आवश्यक हो गया है कि खाद्य पदार्थों के व्यक्तिगत व्यापार को पूरी तरह बंद करके, राष्ट्रीय व्यापार-वाणिज्य चालू करके हर आदमी के लिए दो जून भर पेट खाना मिलने की गारण्टी कर देना। लेकिन सरकार इसके बदले अंत्योदय, अन्नपूर्णा योजना में सस्ता गेहूँ, चावल देने का गुबार उठा कर चिड़ियों को दाना डालने की तरह प्रति व्यक्ति 5-7 किलो खाद्य छिड़क कर खाद्य सुरक्षा का ढोंग कर रही है। अनुदान का मतलब यदि नगद देने की व्यवस्था बैंक के माध्यम से कर देना संभव हो, तब तो जिस उद्देश्य से राशन व्यवस्था निर्मित हुई थी उसका आधार ही नहीं रह जाता है। रह जाती है नग्न खुले बाजार की व्यवस्था। सरकारी उद्देश्य भी यही है। जितना भण्डार खाद्य बफर स्टॉक के रूप में नहीं रखने से चलेगा नहीं उतना रख कर बाकी खुले बाजार में भेज देना ही सरकार का मतलब है। उसे राशन के जरिए देने की व्यवस्था न करके सरकार अनियन्त्रित बाजार की वस्तु बना देना चाहती है। नगद अनुदान का मामूली पैसा लेकर इसी बाजार में खड़ा होना होगा। नियंत्रित रुपया देकर अनियंत्रित कीमत पर खाद्य खरीदना होगा। संकट तो इसी जगह है।

उत्तराखण्ड में आपदा पीड़ितों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए आगे आये स्वास्थ्य कर्मचारी

नई दिल्ली : कलावती सरन बाल चिकित्सालय के लेक्चर हॉल में उत्तराखण्ड में आपदा पीड़ितों के लिए मेडिकल सेवाएं उपलब्ध कराए जाने की तैयारियों के लिए कलावती हॉस्पिटल वर्कर्स यूनियन ने पहलकदमी लेकर लेडी हार्डिंग व कलावती हस्पताल की कर्मचारी व नर्सिज यूनियनों की मदद से एक मीटिंग का आयोजन किया जिसमें डाक्टरों, नर्सिंग, पैरामेडिकल व अन्य वर्ग के कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। मीटिंग की अध्यक्षता अस्पताल के अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षक डा. आर.के.अग्रवाल ने की।

संस्थान के निदेशक डा. अतुल मुरारी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि यूनियनों व मेडिकल सर्विस सेंटर की यह पहलकदमी सराहनीय है और वे निदेशक के नाते आपदा राहत कार्य विशेषकर चिकित्सकीय मदद में हर तरह से सहयोग करेंगे।

विषय की शुरूआत करते हुए वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष व नेशनल पब्लिक हेल्थ अलायंस के दिल्ली राज्य सचिव वी.एस.दहिया ने कहा कि उत्तराखण्ड में बरसात व बादल फटने से हुई भीषण तबाही की वजह से हमारे हजारों भाई-बहनों को ना सिर्फ अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है बल्कि जो बच गये हैं उनका भी सब कुछ तबाह हो चुका है। लोगों के घर-द्वार नष्ट हो गए हैं, रोजगार के साधन खत्म हो गए हैं। वे भोजन, पेयजल, चिकित्सीय सहायता एवं राहत कार्य की उम्मीद में हैं। वहां अब महामारी फैलने के संकेत मिल चुके हैं। श्री दहिया ने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार ने अभी तक भी स्थानीय निवासियों को राहत पंहुचाने के लिए आवश्यक कारवाई नहीं की है। अत: ऐसी स्थिति में जनस्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सकों, नर्सिंग-पैरामेडिकल व अन्य सहायक स्टाफ यानी हर वर्ग के स्वास्थ्यकर्मियों का यह उत्तरदायित्व हो जाता है कि इस आपदा की स्थिति में हम पीड़ितों की हर संभव मदद करें।

स्वास्थ्य कर्मियों को सम्बोधित करते हुए कॉमरेड हरीश त्यागी

मेडिकल सर्विस सेंटर के संयोजक डा. जितेन मुर्मु ने कहा कि फिलहाल 4 डाक्टरों के साथ एक 10 सदस्यीय टीम रुद्रप्रयाग में मेडिकल कैम्प की शुरूआत के लिए भेजी जा चुकी है जो अपने साथ लगभग 3 लाख रुपये की दवाइयां व अन्य सामान लेकर गए हैं। केन्द्रीय ट्रेड यूनियन ए.आई.यू.टी.यू.सी. के दिल्ली राज्य अध्यक्ष कॉ. हरीश त्यागी ने भी बड़े मार्मिक शब्दों में वहां के लोगों की स्थिति का वर्णन किया व समाज के सभी वर्गों से आगे बढ़ कर सहायता जुटाने की अपील की।

उल्लेखनीय है कि कलावती हॉस्पिटल वर्कर्स यूनियन, दिल्ली के स्वास्थ्य कर्मचारियों की अन्य यूनियनों तथा मेडिकल सर्विस सेंटर ने पहले भी उत्तरकाशी भूकंप, उड़ीसा सुपर साईक्लोन व सुनामी जैसी आपदाओं के समय भी मेडिकल कैम्पों का आयोजन किया है और जहां तक सरकार व एन.जी.ओ. ने भी कुछ नहीं किया वहां अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह किया है।

अपील पर फौरन अनुकूल प्रतिक्रिया देते हुए सुचेता कृपलानी हस्पताल से सिस्टर अनुराधा शर्मा व सुनीता आर्य, कलावती सरन बाल चिकित्सालय से प्रयोगशाला तकनीशियन हरीमोहन, संजीव कुमार, यशविन्द्र लोचब, सिस्टर वीना छाबड़ा, सिस्टर गुरमीत कौर व अन्य कर्मचारियों ने स्वयंसेवकों के रूप में कैम्प में जाने लिए अपने नाम दिए। इस कार्य को और बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाने के लिए आगामी जुलाई को जी.बी. पंत हस्पताल में स्वास्थ्यकर्मियों व नर्सिंग स्टाफ की यूनियनों की एक बैठक आयोजित की जा रही है। पीडियाट्रिक्स की विभागाध्यक्षा डा. एस. अनेजा व सी.एम.ओ. मीनाती आचार्य ने भी हर संभव मदद जुटाने का आश्वासन देते हुए कहा कि मामला सिर्फ फौरी तौर पर मेडिकल सहायता का ही नहीं है बल्कि त्रासदी के शिकार लोगों को बाद में भी लम्बे समय तक शारीरिक व मानसिक रिहैबिलिटेशन की जरूरत पड़ेगी। आपदा में मारे गए हजारों लोगों के शोक में दो मिनट का मौन भी रखा गया।

महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों के खिलाफ कन्वेन्शन

राँची (झारखण्ड): महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों के खिलाफ प्रतिरोध तैयारी कमेटी के द्वारा गत् 30 जून को राँची के विधान सभा आवासीय हाल में एक कन्वेन्शन का आयोजन किया गया। इसमें जिले के अनेक बुद्धिजीवी, साहित्यकार, अध्यापक, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, डॉक्टर, वकील एवं सैकड़ों की संख्या में छात्र-छात्राएं एवं युवतियाँ शामिल हुई। कन्वेंशन का उद्घाटन राँची की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. करूणा झा ने किया।

इस कन्वेन्शन की मुख्या वक्ता ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन की अखिल भारतीय अध्यक्ष छाया मुखर्जी थीं। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि आज झारखण्ड सहित पूरे देश भर में महिलाओं की स्थिति अत्यंत ही दयनीय हो गई है। पूरे देश में बलात्कार, दहेज हत्या, मानव तस्करी और भ्रूण हत्या जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बलात्कार की घटनाओं में लगातार हो रही बढ़ोतरी से आज हर परिवार एक खौफ के साए में घिरता चला जा रहा है। आज स्कूल, कॉलेज, आफिस, घर, मुहल्ला कहीं भी लड़कियाँ खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही हैं। टी.वी. विज्ञापन, सिनेमा से अश्लीलता परोसी जा रही है। अश्लील पोस्टरों और बड़े-बड़े अश्लील होर्डिंग की भरमार लगी हुई हैं। इण्टरनेट से लेकर बच्चों के विडियो गेम तक में भी अश्लीलता को देकर बचपन से ही विकृत मानसिकता पैदा की जा रही है। शराब की दुकानें हर गली और चौक-चौराहों में खोली जा रही हैं और खुले आम बच्चों और नौजवानों को नशे का आदी बनाया जा रहा है। इन सब के जरिये उनकी नैतिक रीढ़ तोड़ दी जा रही है। लेकिन यह महज एक इत्तफाक नहीं है बल्कि ये सब एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। जानबूझ कर छात्र-नौजवानों को नशाखोरी और अश्लीलता की दलदल में फंसाया जा रहा है ताकि उनका ध्यान समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और उनके समाधान की ओर न जा सके।

उन्होंने इन समस्याओं के खिलाफ एक सशक्त जनआन्दोलन तैयार करने का आह्वान किया। हर स्कूल, कॉलेज, गली व मुहल्ले में जाकर लोगों को जागरूक करते हुए जन कमेटी तैयार करने पर जोर दिया ताकि महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार पर विराम लगाया जा सके।

ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन की झारखण्ड राज्य सचिव कॉ. केया डे ने अध्यक्षता की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राँची विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के भूतपूर्व प्रधानाध्यापक अशोक प्रियदर्शी और जाने माने बुद्धिजीवी पंकज थे। कार्यक्रम के अंत में 27 सदस्यीय ''नारी सुरक्षा संघर्ष कमेटी'' का गठन किया गया जिसकी कन्वीनर कॉमरेड केया डे को बनाया गया।

युवा संगठन एआईडीवाईओ का 47वां स्थापना दिवस मनाया गया

26 जून को ऑल इण्डिया डेमोक्रेटिक यूथ आर्गेनाइजेशन (एआईडीवाईओ) स्थापना दिवस पर भुवनेश्वर, ओडिशा में राज्य स्तरीय विशाल जुलूस

जौनपुर में लगाया युवा कैम्प

एआईडीवाईओ जिला कमेटी जौनपुर, उ.प्र. द्वारा अपने 26 जून-47वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जगन्नाथ साहू इण्टर कॉलेज, गणेरिहा, महाराजगंज, जौनपुर में जिला स्तरीय यूथ कैम्प आयोजित किया गया। कैम्प में खेलकूद, गीत-संगीत के अलावा परिचर्चा भी आयोजित की गई। परिचर्चा के एक विषय था आजादी आन्दोलन में गांधीजी और भगत सिंह दोनों में से किसका रास्ता जनता के लिए सही था और दूसरा विषय था वर्तमान व्यवस्था में बेरोजगारी का समाधान सम्भव है कि नहीं।

मुख्य अतिथि एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) के जिला सचिव कॉमरेड बेचन अली। मुख्य वक्ता आईडीवाईओ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कॉमरेड दीपक कुमार ने एआईडीवाईओ को युवा आन्दोलन का अग्रगामी बताते हुए विस्तार से चर्चा की। कैम्प में एआईडीवाईओ के राज्य सचिव कॉमरेड रविशंकर भी मौजूद थे। संचालन एआईडीवाईओ के जिला अध्यक्ष कॉमरेड महेन्द्र कुमार मौर्य ने किया। बरसात की विकट स्थिति के बावजूद सैकड़ों नौजवानों ने बड़े जोश और उत्साह के साथ कैम्प में भागीदारी की। इण्टरनेशनल गान के साथ कैम्प का समापन हुआ।

मुरादाबाद (उ.प्र.) में सभा

ऑल इण्डिया डी.वाई.ओ. का 47 वां स्थापना दिवस जलकल कर्मचारी संघ कार्यालय, मुरादाबाद में 27 जून को मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित सभा की अध्यक्षता उ.प्र. राज्य उपाध्यक्ष कॉ. राजेन्द्र सिंह एडवोकेट ने की तथा संचालन संगठन के जिला उपसचिव कॉ. मो. गौरी एडवोकेट ने किया। सभा को मुख्य वक्ता के रूप में संगठन के उ.प्र. राज्य अध्यक्ष कॉ. हरकिशोर सिंह ने सम्बोधित किया। सभा में मुरादाबाद, जिला अमरोहा, जिला सम्भल के सक्रिय सदस्यों ने हिस्सा लिया। सभा को सम्बोधित करते हुए मुख्य वक्ता कॉ. हरीकिशोर ने कहा कि आज हमारे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में युवाओं की स्थिति बहुत खराब है। सपा की प्रदेश सरकार बेरोजगार युवाओं के साथ छल कर रही है। सपा ने युवाओं को झूठे वादे देकर सत्ता हथिया ली लेकिन अब बेरोजगारों की कोई चिन्ता नहीं हैं। इस बात को युवाओं को समझना होगा। तरह-तरह की बंदिशें लगा कर तथा परीक्षाएं करके सरकार काबिल डिग्री धारक युवाओं को नाकाबिल साबित करना चाह रही है ताकि अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा जा सके। उन्होंने आगे कहा कि सारी अलामतों की जड़ यह पूँजीवादी व्यवस्था है। इसमें सरकार बदलने से जनविरोधी नीतियां नहीं बदलती हैं। इसलिए इन जनविरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदेशव्यापी सशक्त सचेत युवा आन्दोलन गठित करना होगा और संगठन को गाँव के स्तर से लेकर राज्य स्तर तक मजबूत बनाना होगा। सभा में उत्तराखण्ड राज्य में मारे गए लोगों के प्रति संगठन ने गहरा दुख प्रकट किया और अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए दो मिनट का मौन रखा। सभा को एडवोकेट विनोद सिंह, एडवोकेट धर्मपाल सिंह सैनी, एडवोकेट दीपा शर्मा, गम्भीर सिंह, शाह आलम, नौबहार सिंह, नवाब अली, मोहसिन खान, आसिफ, राकेश शर्मा आदि ने सम्बोधित किया।

सड़क पर उतरे ग्रामीण सफाई कर्मचारी

पक्का करने, न्यूनतम वेतन देने आदि अपनी ज्वलंत मांगों को बुलन्द करते हुए ऑल इण्डिया यूटीयूसी से सम्बन्धित ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन द्वारा अटेली, नारनौल (हरियाणा) में गत दिनों विरोध प्रदर्शन किया गया।

कम्पलसरी ऑन लाइन एडमिशन के खिलाफ

छात्रों का विरोध प्रदर्शन

बडोदरा (गुजराज) में एमएस यूनिवर्सिटी में कम्पलसरी ऑन लाइन एडमिशन के फरमान के खिलाफ 14 जून को ऑल इण्डिया डीएसओ द्वारा प्रदर्शन किया गया और मैन्युअल एडमिशन के विकल्प की अपनी ज्वलंत मांगों को बुलन्द करते हुए ज्ञापन दिया गया। पिछले साल ऑन लाइन एडमिशन के ओडिशा सरकार के फरमान के खिलाफ वहां के हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था।

समैस्टर सिस्टम खत्म करने का छात्रों द्वारा स्वागत

बडोदरा (गुजराज): भावनगर यूनिवर्सिटी द्वारा इस सत्र से समैस्टर सिस्टम खत्म करने के फैसले का स्वागत करते हुए गत दिनों ऑल इण्डिया डीएसओ के नेतृत्व में छात्रों ने यहां प्रदर्शन किया। संगठन ने मांग की कि अन्य यूनिवर्सिटियों को भी इस कदम का अनुसरण करना चाहिए क्योंकि समैस्टर सिस्टम के चलते छात्रों को पढ़ाई का पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है।

शिक्षा के निजीकरण के दुष्प्रभाव पर सेमिनार

इन्दौर (म.प्र.): गत दिनों यहां शिक्षा के निजीकरण के दुष्प्रभाव पर सेमिनार हुआ। अभिनव कला समाज परिसर में हुए कार्यक्रम में मुख्य वक्ता अखिल भारतीय शिक्षा बचाओ समिति के राजस्थान प्रभारी राजमल शर्मा, डीएवी के पूर्व कुलपति एए अब्बासी व डॉ. शरद पगारे थे। राजमल शर्मा ने सेमिनार को सम्बोधित करते हुए कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्राइवेट स्कूलों में 25 प्रतिशत गरीब बच्चों को दाखिला देने का प्रावधान है जिनकी फीस केन्द्र सरकार देगी। लेकिन इसका फायदा भी निजी स्कूल को ही मिलेगा। यदि सरकार इस फीस के तौर पर दिया जाने वाला पैसा सरकारी स्कूलों के विकास पर खर्च करे तो ज्यादा बेहतर होगा। वरना ऐसे तो एक दिन सारे सरकारी स्कूल खत्म हो जाएंगे।

उन्होंने कहा कि कुछ कानून शिक्षा के लिए घातक बन चुके हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की नई सिफारिश में अब टीचर्स को स्टूडैण्ट्स और प्रिंसिपल्स रैंकिंग देंगे। इसके बाद उन्हें सैलेरी दी जाएगी। इससे टीचर्स बेहतर तरीके से बच्चों को पढ़ा नहीं पायेंगे। किसी छात्र को फेल किये बिना अगली कक्षा में कर देने की नीति से शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है।

एए अब्बासी ने कहा शिक्षा बचाव के लिए अलग-अलग ग्रुप बनाने होंगे। दूसरे देशों में प्राइवेट कॉलेज का कंसेप्ट नहीं होता है। केजी से पीजी तक मुफ्त या सस्ती एजुकेशन देने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। हमारे देश में भी इस तरह के बदलावों के लिए शिक्षा बचाओ आन्दोलन की शुरूआत हो चुकी है। डॉ. शरद पगारे ने कहा कि आजादी से पहले भी देश में प्राइवेट संस्थान थे और उनमें शिक्षा के जरिए इन्सान बनाने की प्रक्रिया होती थी। आज शिक्षा को पूरी तरह कमर्शियल बना दिये जाने से इस प्रक्रिया को बाधित कर दिया गया है।

ड्राइंग कम्पीटिशन आयोजित

बुढ़लाडा (पंजाब) में गत दिनों ऑल इण्डिया डीएसओ की ओर से छात्रों की चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई और प्रतिभागियों में से विजेताओं को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया गया। इस अवसर पर संगठन के दिल्ली राज्य अध्यक्ष कॉमरेड भास्करानन्द भी मौजूद थे।

आशा कार्यकर्ताओं की समस्याओं के समाधान बारे डीसी को ज्ञापन सौंपा

भिवानी : ऑल इण्डिया यूटीयूसी से सम्बन्धित आशा कार्यकर्ता यूनियन के बैनर तले आशा कार्यकर्ताओं ने 18 जून को यहाँ लघुसचिवालय पर प्रदर्शन किया। उन्होंने कम से कम 7000 रुपये मासिक वेतन देने, सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, स्कीम का स्वास्थ्य विभाग में विलय करने, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने, साल में कम से कम दो वर्दियां देने, हस्पतालों में अलग रूम और रात को सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध करने, बीमार पड़ने पर सवेतन अवकाश और मृत्यु या दुर्घटना होने पर उचित मुआवजा देने की माँग करते हुए उपायुक्त जिला भिवानी की मार्फत मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा।

आशा कार्यकर्ता हाथों में माँग पट्टिकाएं लिए हुए नारे लगाती हुई शहर में प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुँची। वहाँ गेट पर जुलूस सभा में बदल गया। सभा को ऑल इण्डिया यूटीयूसी के जिला कमेटी सदस्यों राजकुमार व धर्मवीर सिंह और आशा कार्यकर्ता यूनियन की नेत्री गुड्डी ने सम्बोधित किया।

यूनियन नेताओं ने कहा कि आशा कार्यकर्ता केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) स्कीम के तहत हस्पतालों व फिल्ड में 8-9 घण्टे अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। परिवार का गुजारा चलाने के लिए कोई दूसरा काम करने का समय भी उन्हें नहीं मिल पाता है। आशा कार्यकर्ता सरकारी काम करती हैं लेकिन सरकार फिर भी अपना वर्कर-कर्मचारी नहीं मानती है, बल्कि वालन्टियर कहा जाता है। आशा कार्यकर्ताओं का बेरहम शोषण-उत्पीड़न हो रहा है।

आशा वर्करों ने अपनी समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की देखभाल करना, बच्चों को टीके लगवाना, आयरन आदि की गालियाँ खिलाना, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि बीमारियों से बचने के बारे में जागरूक करना और प्रसव के समय हस्पताल पहुँचाना, रिपोर्ट तैयार करना आदि विभिन्न कार्य उनके जिम्मे हैं। इतनी कड़ी मेहनत करने पर भी सरकार प्रति केस मामूली सी प्रोत्साहन राशि देती है जो 1000 रुपये महीना भी नहीं पड़ती है। वह भी कोई नियमित, निश्चित नहीं है और उसके लिए भी ए.एन.एम. और गाँव के सरपंच के दस्तखतों के लिए भटकना पड़ता है। इसके बाद डाक्टरों की कलम चलती है। यह खुद सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन या मनरेगा के तहत दिये जाने वाले वेतन से भी बहुत ही कम है। आज की आकाशछूती महंगाई में इतने थोड़े से पैसों से किसी का गुजारा नहीं होता है। दिन-रात काम करने वाली आशा कार्यकर्ता कमजोर तबके की महिलाएं हैं और उनकी दशा बेहद सोचनीय है। सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन या मनरेगा के तहत दिये जाने वाले वेतन जितना मेहनताना तो कम से कम देना ही चाहिए। हाजिरी रजिस्टर, मासिक बंधे वेतन, महंगाई के हिसाब से सालाना बढ़ोतरी, जीवन बीमा, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, पेन्शन, वर्दी, सवेतन अवकाश, बीमार पड़ने पर इलाज आदि सामाजिक सुरक्षा उपायों व सुविधाओं से भी वे वंचित हैं और नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है। आशा कार्यकर्ताओं को भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना, जीने लायक वेतन देना और आई.एल.सी. में ट्रेड यूनियनों द्वारा दिये गये सुझावों व सिफारिशों को लागू करना केन्द्र व राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बनती है। केन्द्र व राज्य सरकार और अधिकारियों को इन समस्याओं के बारे में कई बार बताया जा चुका लेकिन उनका रवैया आशा वर्करों के प्रति घोर निराशाजनक, संवेदनहीन और बेरुखा है।

वक्ताओं ने आशा कर्मियों को अपनी मांगों के लिए आन्दोलन तेज करने का आह्वान करते हुए कहा कि आन्दोलन के सिवाय और कोई विकल्प नहीं है।

प्रदर्शन में काफी आशा कार्यकर्ता शामिल थी जिनमें कमला, संतोष, सुशीला आदि प्रमुख थी।

नागरिक सुविधएं मुहैया कराने के लिए पटना में नागरिक कन्वेन्शन

देश की आम जनता जब महंगाई की असहनीय पीड़ा से कराह रही है, वैसे में सरकार और उसकी विभिन्न एजेंसियां/संस्थान आम अवाम पर विभिन्न प्रकार के टैक्सों का बोझ लादकर उसके जले पर नमक छिड़क रहे हैं। बिहार और उसकी राजधानी पटना की आम जनता भी इससे अलग नहीं है। हाल के दिनों में पटना नगर निगम द्वारा होल्डिंग टैक्स में मनमाने तरीके से सौ फीसदी यानी दोगुनी वृद्धि की गयी है। सिर्फ इतना ही नहीं, जमीनों के सरकारी मूल्य को बढ़ाकर रजिस्ट्री फीस में इजाफा किया गया है। साथ ही मकान मालिक एवं किरायेदार के बीच रजिस्ट्री से इकरारनामा के नाम पर किराया राशि का दो फीसदी स्टाम्प ड्यूटी तथा कूड़ा उठाव व जल आपूर्त्ति की दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की गयी है। हद तो यह है कि परती जमीन से भी होल्डिंग टैक्स लेने का निर्णय लिया गया है। दूसरी तरफ शहर की सफाई, पार्कों के रख-रखाव, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, पेयजल की आपूर्त्ति तथा अन्य नागरिक सुविधाएं मुहैया कराने के सिलसिले में पटना नगर निगम का रेकार्ड काफी खराब रहा है। नगर निगम के विभिन्न वार्डों में सड़कों एवं गलियों से कूड़ा-कचरा के उठाव की समुचित व्यवस्था नहीं है। मुख्य सड़कों की बात छोड़ दी जाए तो शहर के अधिकांश इलाकों, मुहल्लों, सड़कों एवं गलियों में गन्दगी का अम्बार लगा रहता है। भूगर्भ नालों, खुले नालों, चैम्बरों एवं उपचैम्बरों की प्रतिवर्ष बरसात के पहले सफाई करने की सरकारी घोषणाओं के बावजूद व्यवहार में उसका पालन नहीं किया जाता और मात्र खानापूर्ति की जाती है। फलस्वरूप शहर के अधिकांश मुहल्ले बरसात के दिनों में नरक का दृश्य उपस्थित करते हैं। पानी की समुचित आपूर्त्ति की व्यवस्था करने में भी पटना नगर निगम एवं जल पर्षद सक्षम साबित नहीं हो पा रहा है। सड़कों एवं गलियों में रात्रि में समुचित प्रकाश (बिजली) का प्रबंध न के बराबर है। मुख्य सड़कों पर भी इसकी कमी खलती है। मालियों/कर्मचारियों की व्यवस्था नहीं होने से अधिकांश पार्क/उद्यान दयनीय हालत में हैं। मच्छरों के प्रकोप से बचने के लिए समय-समय पर फोगिंग मशीनों द्वारा दवा का छिड़काव नहीं होता। नगर निगम में सफाई व्यवस्था और नागरिक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए जरूरी स्थायी कर्मचारियों की भारी कमी है।

पटना नगर निगम के इन गैर जनतांत्रिक व जनविरोधी कदमों के विरोध में नागरिकों ने संघर्ष समिति गठित कर संघर्ष का आगाज किया है। पिछले दिनों दिनकर गोलम्बर, नाला रोड पर नागरिकों का धरना आयोजित हुआ और इसकी अगली कड़ी में 4 जून को आई. एम. ए. हॉल में नागरिक कन्वेन्शन का आयोजन किया गया।

कन्वेन्शन को अन्य लोगों के अलावा एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) की पटना जिला सचिव कॉमरेड साधना मिश्रा तथा जिला कमिटी सदस्य कॉमरेड सूर्यकर जितेन्द्र ने संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अपने को लोक कल्याणकारी होने का दावा करने वाली सरकारें धीरे-धीरे सामाजिक जिम्मेवारियों से मुंह मोड़ती जा रही हैं और उन्हें निजी हाथों में सौंपने की ओर बढ़ रही हैं। फलस्वरूप बहुसंख्यक जनता भयंकर गरीबी, अभाव एवं तबाही में जीवन बसर करने को अभिशप्त हो गयी है। सुशासन एवं न्यायपूर्ण विकास की ढपोरशंखी घोषणाएं करने वाली वर्तमान बिहार सरकार भी निजीकरण, उदारीकरण एवं भूमंडलीकरण की उन्हीं जनविरोधी,

पूंजीपति परस्त नीतियों पर अमल कर रही है। वक्ताओं ने कहा कि आम जनता को जरूरी नागरिक सुविधाएँ मुहैया कराने में सरकार, प्रशासन एवं नगर निगम की उदासीनता और उन पर टैक्सों का बोझ लादने में उनकी सक्रियता ने आम जनता के समक्ष जन संघर्ष के सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। कन्वेन्शन को अनेक सामाजिक-राजनैतिक कार्यकर्ताओं और पटना नगर निगम के कई वार्ड पार्षदों ने भी संबोधित किया। सभी वक्ताओं ने राज्य सरकार, पटना नगर निगम की जनविरोधी कार्रवाइयों के खिलाफ तथा नागरिक सुविधाएं मुहैया कराने के सवाल पर एकताबद्ध आंदोलन विकसित करने के लिए नागरिकों से अपील की। कन्वेन्शन का मूल प्रस्ताव नागरिक संघर्ष समिति के संयोजक मोहन प्रसाद ने पेश किया जबकि संचालन एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) पटना जिला कमिटी सदस्य कॉमरेड अनामिका सहित पांच सदस्यीय अध्यक्ष मंडल ने किया।

मेडिकल कैम्प...

(पृष्ठ 1 का शेष)

और पैरामैडिकल स्टॉफ के द्वारा किया गया। इनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल थे।

पहली जुलाई को विभिन्न राज्यों से आए 11 नए सदस्य पायलट मेडिकल टीम के साथ शामिल हो गए। अगले दिन यानी 2 जुलाई को 7 डॉक्टरों और पैरामैडिक्स की एक मेडिकल टीम एक सेटेलाइट बेस कैम्प स्थापित करने के लिए बांसवाड़ा भेजी गई। रुद्रप्रयाग के बेस कैम्प में 7 डॉक्टरों और पैरामेडिक्स ने 115 मरीजों का इलाज किया जो आसपास के लगभग 16 गाँवों से आए थे।

हमारे शुरूआती सर्वे की पुष्टि मरीजों और उनके रिश्तेदारों द्वारा की गई जिन्होंने खुलासा किया कि गुप्तकाशी, सोन प्रयाग, अगस्तमुनि, चन्द्रापुरी, विजय नगर, बांसवाड़ा और बहुत सी अन्य जगहों पर भारी संख्या में परिवार तबाह हुए हैं। उनके बहुत से पारिवारिक सदस्य लापता हैं जिसकी वजह से लोग भारी मानसिक तनाव में हैं। उन्हें तुरन्त चिकित्सीय मदद की जरूरत है लेकिन अभी भी अन्य मूलभूत जरूरतों की तरह ही उनके पास कोई मदद नहीं पहुँची है। इसलिए 30 जून से ही एमएससी की डिजास्टर मेडिकल रिस्पोन्स टीम द्वारा रुद्रप्रयाग बेस कैम्प में सेवाओं को जारी रखने के साथ-साथ उपरोक्त दूर दराज के और अभी भी कटे हुए गाँवों में मोबाइल टीमें भेजी जा रही हैं।

मेडिकल सर्विस सैण्टर की केन्द्रीय कमेटी विशेषकर सभी जनपरस्त डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों से, खास कर उत्तर भारत के राज्यों से अपील करती है कि वे इस विध्वस्त क्षेत्र के असहाय लोगों की दुर्दशा में उनके साथ खड़े होने के लिए स्वेच्छा से आगे आएं और सभी सही सोच रखने वाले लोगों से अपील करती है कि इस मेडिकल मिशन को तन-मन-धन से सहयोग दें।

प्राकृतिक गैस के दाम...

(पृष्ठ 1 का शेष)

साल 8 डॉलर, दूसरे साल 10 डॉलर, तीसरे साल 14 डॉलर और पिछले दो साल के रेट असल में हूबहू वही होंगे जो रिलायन्स मांग कर रही थी क्योंकि इससे उसे 162000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त मुनाफा होगा। अनुमानित है कि गैस के दामों में हर डॉलर की बढ़ोतरी की वजह से इसकी तिजारियों में कम से कम 74 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इजाफा होगा।

प्राकृतिक गैस के दामों में दुगनी बढ़ोतरी लाजमी तौर पर आम आदमी को बंधक बना देगी क्योंकि इससे खाद, बिजली और रसोई गैस के दामों में बड़ा भारी उछाल आने लगेगा और धीरे-धीरे पेट्रोल-डीजल सहित अन्य पैट्रो पदार्थों के दामों पर भी असर डालने लगेगी। यह मुद्रास्फीतीय दबाव को भी भयावह रूप से बढ़ा देगी जो रोजमर्रे की जरूरी चीजों की बेरोकटोक बढ़ती महंगाई से और आमदनी में लगातार गिरावट से पहले ही बेहाल जिन्दगी को और भी नारकीय बना देगी। भारतीय बुर्जुआ सरकार का यह शैतानीभरा कदम एक बार फिर दिखा देता है कि सरकार कितनी बेशर्मी से एक पर एक ऐसे जनविरोधी और एकाधिकारी पूँजीपतिपरस्त बर्बर आर्थिक कदम संसद को लगातार दरकिनार करते हुए और वह भी बजट के दायरे से बाहर जाते हुए उठा रही है।

इसके जबरदस्त विरोध में उठ खड़े होने और इस फैसले को पूरी तरह वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर करने के लिए सरकार को मजबूर करने के लिए देशव्यापी जोरदार आन्दोलन गठित करने की हम लोगों से अपील करते हैं।

R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-01/1123/2012-2014
Posting at IPMBC on 7–8 and 22–23 Fortnightly Date of Printing : 5 July, 2013

बगहा पुलिस फायरिंग के खिलाफ राज्यव्यापी प्रतिवाद दिवस व बिहार बंद

पटना :पश्चिमी चम्पारण जिले के नौरंगिया थाना अंतर्गत दरदरी गांव में एक युवक के अपहरण व हत्या की आशंका को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों पर बर्बर पुलिस फायरिंग में 7 लोग मारे गये और दर्जनों लोग घायल हुए। एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) सहित अन्य वाम दलों ने इस घटना की कड़ी भर्त्सना करते हुए 26 जून को राज्यव्यापी प्रतिवाद दिवस मनाया और 27 जून को बिहार बंद का आह्वान किया।

26 जून को राज्यव्यापी प्रतिवाद दिवस के अवसर पर एसयूसीआई (कम्युनिस्ट), सीपीआई (एम), सीपीआई (एम-एल), एमसीपीआई (यू) समेत 15 वामपंथी, प्रगतिशील व जनवादी संगठनों ने राजधानी पटना में भगत सिंह चौक से प्रतिरोध मार्च का आयोजन किया। प्रतिरोध मार्च जे. जी. गोलम्बर, फ्रेजर रोड, डाक बंगला चौराहा होते हुए पटना जंक्शन गोलम्बर पहुंच कर एक सभा में तब्दील हो गया। प्रतिरोध सभा को संबोधित करते हुए एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) बिहार राज्य कमिटी सदस्य मणिकांत पाठक ने पुलिस फायरिंग की घटना को प्रशासन की पूर्णत: लापरवाही का नतीजा बताते हुए कहा कि यदि पुलिस ने 8 दिन पहले गुम हुए युवक का पता लगाने की कोशिश की होती तो ग्रामीण पुलिस के प्रति आक्रोशित नहीं हो पाते और गोली चलाने की नौबत ही नहीं आती और न सात लोगों की जानें जातीं।

पार्टी के राज्य कमिटी सदस्य कॉमरेड अरूण कुमार सिंह ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में पूरे प्रदेश में सरकार की जनविरोधी दमनकारी नीतियों के चलते मजदूरों, किसानों, कमजोर तबकों, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों तथा अन्य मेहनतकश वर्गों पर लगातार चलाये जा रहे पुलिसिया जुल्म-अत्याचार की निन्दा करते हुए सरकार एवं पुलिस प्रशासन के खिलाफ सशक्त प्रतिवाद आंदोलन खड़ा करने का आह्वान आम जनता से किया। उन्होंने बगहा पुलिस फायरिंग को पुलिस प्रशासन के जनविरोधी, दमनकारी एवं निरंकुश चरित्र का परिचायक करार देते हुए उसकी तीव्र भर्त्सना की। साथ ही उन्होंने दोषी पुलिस अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा चलाकर उन्हें दंडित करने और फायरिंग में मारे गये लोगों के परिजनों

26 जून को राज्यव्यापी प्रतिवाद दिवस के अवसर पर एसयूसीआई (कम्युनिस्ट), सीपीआई (एम), सीपीआई (एम-एल), एमसीपीआई (यू) समेत 15 वामपंथी, प्रगतिशील व जनवादी संगठनों ने राजधानी पटना में प्रतिरोध मार्च

तथा घायलों को समुचित मुआवजा देने की भी मांग की। राजधानी पटना के अलावा मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, अरवल, बांका, खगड़िया, बेगूसराय, वैशाली आदि जिलों में प्रतिवाद दिवस मनाया। इस मौके पर विभिन्न जिलों में कार्यकर्ताओं ने प्रतिवाद मार्च निकाल कर बर्बर पुलिस फायरिंग की घटना का विरोध किया और राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार नारे लगाये। कई जिलों में पुलिस फायरिंग के खिलाफ मुख्यमंत्री का पुतला भी दहन किया गया। अगले दिन 27 जून को एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) कार्यकर्ता ने राजधानी पटना में जुलूस निकाल कर विभिन्न मार्गों की परिक्रमा की और लोगों से बंद में शामिल होने की अपील की। पार्टी कार्यकर्ता जुलूस में राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ जोरदार नारे लगा रहे थे।

जुलूस का नेतृत्व एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) पटना जिला सचिव तथा राज्य कमिटी सदस्य कॉमरेड साधना मिश्रा, राज्य कमिटी सदस्य कॉमरेड सूर्यकर जितेन्द्र तथा एआईडीएसओ राज्य सचिव कॉमरेड अनिल कुमार ने किया।

राजधानी पटना के अलावा मुजफ्फरपुर, मंगेर, भागलपुर, दरभंगा, अरवल, बांका, खगड़िया, बेगूसराय, वैशाली आदि जिलों में नेता-कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और आम जनता से बंद में शामिल होने की अपील की। इस मौके पर राज्य सचिव कॉमरेड शिव शंकर ने कहा कि सुशासन की रट लगाने वाली नीतीश सरकार आज पूरी तरह से जनविरोधी चरित्र लेकर चल रही है। उन्होंने कहा कि आम जनता के साथ राज्य सरकार के दमनात्मक व्यवहार में तेजी आयी है। सामाजिक न्याय का दंभ भरने वाली नीतीश सरकार अपने जनविरोधी चरित्र के तहत जन आंदोलनों को लाठी-गोली से दबा रही है।

जिक्र किया जा सकता है कि जन आंदोलन के दबाव में राज्य सरकार ने नौरंगिया के थानाध्यक्ष को निलम्बित कर दोषी पुलिस कर्मियों पर हत्या का मुकदमा चलाने, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख व घायलों को 50 हजार रुपये मुआवजा देने की घोषणा करनी पड़ी है।

यूवीसीई छात्र आन्दोलन की जीत, परीक्षाएं स्थगित

बैंगलोर (कर्नाटक): यूनिवर्सिटी विश्वेशवरैया कॉलेज ऑफ इन्जिनियरिंग (यूवीसीआई) छात्रों के आन्दोलन के दबाव में बैंगलोर यूनिवर्सिटी ने नियत परीक्षाएं दो हफ्ते के लिए स्थगित कर दी। परीक्षाएं पूर्वनियत समय अनुसार 24 जून से होनी थी। इससे छात्रों के लिए परीक्षा की तैयारी करने के लिए बहुत ही कम समय मिलता। बैंगलोर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने 18 जून को सम्बन्धित विभागाध्यक्षों और अधिकारियों की मीटिंग बुलानी थी। इस दिन सुबह से ही 500 से अधिक छात्र वीसी कार्यालय के बाहर इकट्ठा हो गए थे। इससे उनकी चिन्ता और समस्या की गंभीरता साफ झलक रही थी। छात्रों के प्रतिनिधियों ने वीसी को ज्ञापन दिया और उनसे अपनी मांगों पर विचार करने का अनुरोध किया। अन्तत: मीटिंग में यूनिवर्सिटी की ओर से छात्रों की मांग मान कर परीक्षाओं का समय बदल कर 8 जुलाई 2013 कर दिया।

यह आन्दोलन यूवीसीई छात्र संघर्ष कमेटी और ऑल इण्डिया डैमोक्रेटिक स्टूडेण्ट्स ऑर्गेनाइजेशन (एआईडीएसओ) के नेतृत्व में हुआ। एआईडीएसओ ने इस कामयाबी के लिए छात्रों को बधाई दी जो सिर्फ उनकी एकता और संगठन की वजह से कामयाब हुआ। छात्र नेताओं ने इसे और भी मजबूत करने की अपील की।

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया(कम्युनिस्ट) की ओर से कॉ. गिरिजेश्वर सिंह द्वारा 3ए/38, डब्ल्यू.ई.ए., करोल बाग. नई दिल्ली-5 से संपादित व प्रकाशित तथा परम्परा प्रिंटिंग प्रेस, बी-70/83, इण्डस्ट्रियल एरिया, लॉरेंस रोड, दिल्ली-35 से मुद्रित, दूरभाष: 011-25726631, Email: sarvaharadrishtikon@gmail.com; sarvaharadrishtikon@yahoo.comE-